

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगौलीघाट में
अगोन बैण्ड से आवलाघाट मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम अगोन
तहसील-गंगौलीघाट जिला-

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अगोन बैण्ड से आवलाघाट परियोजना
के निर्माण हेतु (०.०० हे० आरक्षित वन भूमि, ०.५० हे० सिविल सोयम.भूमि.०.० हे०,
वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल ०.५० हे० वन भूमि का

लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अगोन द्वारा दिनांक 18/6/17 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम अगोन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लोक निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्राम पंचायत अर्गोन

हो *हरिदास*
ग्राम प्रधान *प्रधान*
विद्यो-नामोदित (विधायक)

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगोलीहाट में अगोन बेण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग

77

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम माली
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अगोन बेण्ड से आंवलाघाट परियोजना के निर्माण हेतु (0.50 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.45 हे० सिविल सोयम भूमि 0.36 हे०, वन पंचायत भूमि X हे०) अर्थात् कुल 1.31 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत माली द्वारा दिनांक 22.6.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम माली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो ग्राम पंच० वि० अ०
हो क्षेत्र
ग्राम माली - गंगोलीहाट
जिला - पिथौरागढ़

22.6.17
हो 50/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 22/1/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	जगदीश चंद	जगदीश चंद
	नवीन सिंह	नवीन सिंह
	सुरेश जोशी - ग्राम प्रधान	सुरेश जोशी
	भास्कर देवी	भास्कर देवी
	कमल देवी	कमल देवी
	सत्य देवी	सत्य देवी
	हनुमन्त देवी	हनुमन्त देवी
	गोपाल सिंह - बाबा भे.	गोपाल सिंह
	सावित्री देवी	सावित्री देवी
	मदन शाह, शाह देवी	मदन शाह
	महेश चंद	महेश चंद
	श्री देवी	श्री देवी
	जोगी राम	जोगी राम
	गोपालशर्मा	गोपालशर्मा

कै. 22/1/17

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में अगोन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पोरवरी
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अगोन बैण्ड से आंवलाघाट परियोजना के निर्माण हेतु (1.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.35 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.0 हे० वन पंचायत भूमि X हे०) अर्थात् कुल 1.35 हे० वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोरवरी द्वारा दिनांक 22.6.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोरवरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को न देना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ग्रा-23/330
ग्राम सचिव
वि०स०-पिथौरागढ़
जिला-पिथौरागढ़

ह०/—
ग्राम प्रधान
Block-Candigarh (B.N.)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Dhirendra Kumar Joshi
→ G.H.O / -dhan
Pokhari Bhaang
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगौलीहाट में
अगौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जल्थुडी
तहसील गंगौलीहाट जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र आंवलाघाट
उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अगौन बैण्ड से परियोजना
के निर्माण हेतु (1.5 हे० आरक्षित वन भूमि, ०.3० हे० सिविल सोयम भूमि, ०.०० हे०,
वन पंचायत भूमि X हे०) अर्थात् कुल 1.8० हे० वन भूमि का
जोके निमाण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जल्थुडी द्वारा दिनांक.....को
सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम जल्थुडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ जल्थुडी वि० अ०
ग्राम सचिव
वि० अ० - गंगौलीहाट
जिला - पिथौरागढ़

जल्थुडी
ह०/ जल्थुडी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गंगौलीहाट
जिला - पिथौरागढ़

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 21/4/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जल्पाडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	वृद्ध लालू देवी वाड	वृद्ध लालू देवी
	दोशपास सिंह	दोशपास सिंह
	मथुराशरण	मथुराशरण
	रामसिंह	रामसिंह
	मगवान सिंह	मगवान सिंह
	दान सिंह	दान सिंह
	सोहन सिंह	सोहन सिंह
	खन्नु सिंह	खन्नु सिंह
	मुक्केश सिंह	मुक्केश सिंह

श. लाल देवी
 मुखिया

ह0/-
 ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में
अगौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बोयल
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अगौन बैण्ड से आंवलाघाट परियोजना के निर्माण हेतु 1.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.25 हे० सिविल सोयम भूमि 5.06 हे० वन पंचायत भूमि ~~—X—~~ हे० अर्थात् कुल 1.756 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बोयल द्वारा दिनांक 20.6.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बोयल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 29/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बोयल.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	भगवान सिंह	भगवान सिंह
	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
	श्रीमती राजा देवी	श्रीमती राजा देवी
	गोबिन्द राम	गोबिन्द राम
	राम सिंह	राम सिंह
	Ram Singh	Ram Singh
	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
	गोबिन्द सिंह	गोबिन्द सिंह
	गुलार सिंह	गुलार सिंह
	भदन सिंह	भदन सिंह
	भदन सिंह	भदन सिंह
	अवनि राय	अवनि राय

इमरा देवी
ग्राम पंचायत बोयल
वि०ख०-गमोलीहाट (पि०)

ह०/-

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में
अगोन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुंगर नौला
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र आंवलाघाट
उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अगोन बैण्ड से परियोजना
के निर्माण हेतु 0.917 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.395 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे०,
वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल 1.312 हे० वन भूमि का
लोके निमाण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुंगर नौला द्वारा दिनांक 19.6.17 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम सुंगर नौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लोके निमाण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / —
ग्राम सचिव

सुंगर नौला
ग्राम पंचायत अध्यक्ष
पिथौरागढ़ जिला (पिथौरागढ़)
ह० / —
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

ग्राम पंचायत खुंगरनीला

[illegible]

हमा देवी

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बोयल
पिछा-हठ/घाट (पिथौरागढ़)
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पिछौरागढ़ में विकासखण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत अजौन बैण्ड से आँवलाघाट मोटर मार्ग किमी 0.00 से किमी 17.7

प्रपत्र-23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गंगोलीहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, गंगोलीहाट

उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत अजौन बैण्ड से आँवलाघाट मोटर मार्ग में (प. 5.14 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.245 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.95 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 8.059 हे० वन भूमि) का लो. नि. वि. बैरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गंगोलीहाट) की दिनांक 25/6/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1- | श्री <u>वैभव गुप्ता</u> | उपजिलाधिकारी | <u>गंगोलीहाट</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>रमेश कुमार</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>बैरीनाग</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>विक्रम चन्द</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>गंगोलीहाट</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>पद्मवती प्रसाद</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>पाली, बोरवल</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

अजौन बैण्ड से आँवलाघाट मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.059 हे० वन भूमि

लो. नि. वि. बैरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बैरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से, उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत
अग्रोहाट से मावलाहाट मॉटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 8.057
हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिछौराहाट..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद.....

16/08/2014
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
गंगोलीहाट (पिछौराहाट)

अध्यापक
(अग्रोहाट प्रखण्ड)
श्री 1/5 मावला सुहाग
पाना वापस

16/08/2014
उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट

तहसीलदार
गंगोलीहाट

वन अधिकारी
गंगोलीहाट वन क्षेत्र
पिछौराहाट वन प्रभाग पिछौराहाट

वन अधिकारी
पिछौराहाट

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector- **Pithoragarh**

No---

Dated----- 07-09-2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **8.057** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Berinag** (name of user agency) for **Agron Band To Awalnghat Moter road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Pali, Pokhari, Jatudi, Boyal, Sungarnola, Agron** village (s) in **Gangolihat** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **8.057** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


Signature
जिलाधिकारी

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated--- 07-09-07

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 8.057 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D

Berinag (name of user agency) for **Agron Band To Awalaghat Moter road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Pali, Pokhari, Jatudi, Boyal, Sungarnola, Agron** village (s) in **Gangolihat** tehsils. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.057 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.


Signature
जिलाधिकारी

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **C. Ravishankar** I.A.S deputy commissioner **Pithoragarh** on dated **07.09.2017** at time **10.30 AM** in which application claiming rights in area measuring 8.057 hect for the construction of **Agron Band To Awalanghat Moter road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Gangolihat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place **Pithoragarh**

Dated: **07.09.2017**


Deputy Commissioner cum-Chairman
पिथौरागढ़
District Level Committee

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

जिलास्तरीय समिति-पिथौरागढ़

उप खण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील बेरीनाग) की दिनांक 7/9/2017..... .. को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी० रवि शांकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

- 1-श्री सी० रवि शांकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष।
- 2-श्री विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य।
- 3-श्री पी० बी० सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव।
- 4-श्री/श्रीमती ~~विदेन्द्र खिखर~~ जिला पंचायत क्षेत्र पोखरी सदस्य।

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अग्रोन बैण्ड से आवलाघाट मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.057 हे० वनभूमि को लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी
अध्यक्षप्रभागीय वनाधिकारी
सदस्यजिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिवसदस्य जिला पंचायत
सदस्यजिलाधिकारी
पिथौरागढ़